

आर्थिक विकास के निर्धारण तत्व

(Determinants of Economic Development)

प्रो० हेरोड एवं डोमर ने आर्थिक विकास के चार सहायक तत्व माने हैं जो इस प्रकार हैं—(1) जनसंख्या वृद्धि की दर, (2) औद्योगिक विकास की दर, (3) पूँजी उत्पादन-अनुपात, (4) बचत एवं आय का अनुपात ।

श्रीमती जान राबिन्सन का मत है कि आर्थिक विकास एक स्वतः प्रारम्भ होने वाली प्रक्रिया है इसलिये प्राथमिक तत्वों के विपरीत, अनुपूरक तत्वों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये क्योंकि विकास को अन्तिम रूप देने का उत्तरदायित्व इन्हीं तत्वों पर होता है । उनकी दृष्टि में जनसंख्या एवं उत्पादन की दर का अनुपात और पूँजी निर्माण की दर, दो सहायक तत्व आर्थिक विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं ।

प्रो० रिचार्ड टी० गिलने के अनुसार आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं—(1) जनसंख्या वृद्धि (Growth of population),

आर्थिक विकास

(2) प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources), (3) पूँजी संचय (Accumulation of Capital), (4) उत्पादन की विशिष्टता (Specialization of production) तथा (5) तकनीकी प्रगति (Technological progress)।

प्रो० मायर एवं बाल्डविन का मत है कि यद्यपि आर्थिक विकास को बनाये रखने के लिये वांछित निर्धारक आर्थिक तत्वों की एक सूची तैयार की जाये तो वह काफी लम्बी बन सकती है परन्तु इनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं—(1) तकनीकी प्रगति एवं पूँजी संचय (Technological progress and capital accumulation), (2) प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources), (3) जनसंख्या तथा (4) संसाधनों का लचीलापन (Flexibility of resources)।

आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व

आर्थिक तत्व (Economic Factors)	गैर-आर्थिक तत्व (Non-Economic Factors)
1. जनसंख्या	1. सामाजिक तत्व
2. प्राकृतिक संसाधन	2. सांस्कृतिक तत्व
3. पूँजी निर्माण एवं पूँजी उत्पादन अनुपात	3. संस्थागत तत्व
4. उद्यमशीलता	4. स्थिर एवं कुशल शासन
5. प्राविधिकी विकास	5. अन्तर्राष्ट्रीय दशायें
6. व्यावसायिक ढाँचा	
7. विदेशी पूँजी	

संक्षेप में आर्थिक विकास के कुछ सर्वमान्य निर्धारक तत्वों का वर्णन नीचे दिया जा रहा है—

जनसंख्या

जनसंख्या का मानवीय श्रम देश की वह शक्ति है जिस पर देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। ह्वीपील महोदय का कथन है कि “किसी भी देश की वास्तविक सम्पत्ति उस देश की भूमि या पानी में नहीं वनों या खानों में नहीं पक्षियों या पशुओं के झुण्डों में नहीं और न ही डालरों के ढेर में आँकी जाती है बल्कि इस देश के स्वस्थ, सम्पन्न व सुखी पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों में निहित है।”¹

आर्थिक विकास के लिए न तो जनाधिक्य (overpopulation) और न न्यून जनसंख्या उचित मानी गयी है बल्कि अनुकूलतम जनसंख्या (optimum population) उपयुक्त आँकी गई है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण आर्थिक विकास का क्रम असन्तुलित ढंग से होता है क्योंकि जनसंख्या में होने वाली अधिकांश वृद्धि को अन्ततः कृषि कार्य में संलग्न रहना पड़ता है। विकासशील देशों में पूँजी की कमी के कारण अतिरिक्त जनसंख्या को कृषि के अतिरिक्त उद्योगों में लगाना कठिन हो जाता है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण उत्पादन प्रति व्यक्ति कम होता है। विकासशील देशों

1. A nation's true wealth is not in its land waters, not in forests and mines, not in its flocks and herds, not in its dollars, but in its wealthy and happy men, women and children.”

—Whipple.

का लगभग 50 से लेकर 60% राष्ट्रीय आय कृषि से ही प्राप्त होती है। उद्योगों का विकास रुक-रुक कर होता है।

अत्यधिक जनसंख्या के कारण उत्पादन की न्यूनता, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति कम, खाद्यान्नों की न्यूनता, पूँजी की न्यूनता, बेरोजगारी की समस्या, देश का असन्तुलित विकास होते देखा गया है।

प्राकृतिक संसाधन

राष्ट्र के विकास के लिये प्राकृतिक संसाधनों की उपस्थिति मुख्य स्थान रखती है। मुख्य रूप से स्वीकार किया गया है कि अन्य बातों के समान होने पर जिस देश के पास प्राकृतिक संसाधन जितने ही अधिक होंगे, उस देश का आर्थिक विकास उतना ही शीघ्र होगा। प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं उनके लिये रिचार्डगिल ने स्पष्ट किया है कि— जनसंख्या एवं श्रम की पूर्ति की भाँति प्राकृतिक संसाधन भी एक देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उपजाऊ भूमि एवं जल के अभाव के बिना कृषि का विधिवत् विकास नहीं हो पाता है। लोहा, कोयला या अन्य खनिजों की अनुपस्थिति में तीव्र औद्योगिकरण का स्वप्न अधूरा ही बना रहेगा। जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों की प्रतिकूलता के कारण आर्थिक क्रियाओं के विस्तार में अवरोध उत्पन्न करते हैं। वास्तव में प्राकृतिक संसाधनों का किसी भी देश के आर्थिक विकास को सीमित करने अथवा प्रोत्साहित करने में एक मुख्य निर्णायक तत्व होता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों की बाहुल्यता ही पर्याप्त नहीं है बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित ढंग से विदोहन किया जाना भी अति आवश्यक है।

पूँजी संचय

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये पूँजी का संचय (Capital accumulation) अति आवश्यक है। प्रो० कुजनेट्स ने यह स्पष्ट किया है कि "पूँजी एवं पूँजी संचय आर्थिक विकास की एक आधारभूत आवश्यकता है।" प्रो० नर्कसे ने स्पष्ट किया है कि "पूँजी निर्माण आर्थिक विकास की एक पूर्व-आवश्यकता है।" किसी भी देश के आर्थिक विकास में सड़कों, भवनों, कल-कारखानों मशीनों, बाँध, नहरों, कच्चा माल एवं उपकरण के लिये पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। इनका निर्माण पूँजी से ही सम्भव है। जिस देश के पास संसाधन जितने ही अधिक होंगे, अन्य बातें समान रहने पर उसका आर्थिक विकास उतना ही अधिक एवं तीव्र होगा। विकासशील देशों के पास पूँजी की कमी होने से उनके देश का आर्थिक विकास बहुत धीमी गति से होता रहता है। वास्तव में पूँजी की पर्याप्तता एवं न्यूनता, वर्तमान समय में, अमीर एवं गरीब के बीच पाए जाने वाले अन्तर का कारण है।

तकनीकी ज्ञान एवं प्रगति

किसी भी देश की उन्नति एवं आर्थिक विकास में तकनीकी प्रगति एवं नव-प्रवर्तन (Technological progress and innovations) मुख्य स्थान रखते हैं। प्रो० गिल ने स्पष्ट किया है कि किसी भी देश की तकनीकी प्रगति व नव-प्रवर्तन के लिये चार तत्व आवश्यक हैं—

- (अ) वैज्ञानिक अभिरुची (Scientific attitude), (ब) ऊँच शैक्षणिक स्तर,
- (स) नव-प्रवर्तनों को व्यावहारिक रूप देना तथा (द) उद्यमशीलता

तकनीकी प्रगति से प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त विदोहन (Utilization) के द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होकर जनसंख्या का स्तर ऊँचा उठाया जा सकता है। तकनीकी ज्ञान उत्पादन की विधियों में मौलिक परिवर्तन लाकर आर्थिक विकास में सहायक हो सकता है। विकसित देशों में तकनीकी प्रगति के कारण जन-जीवन उन्नत तथा सम्पन्न होता है। नव-प्रवर्तन (innovation) के द्वारा कृषि उत्पादन में प्रति हैक्टर वृद्धि हुई है जिस कारण जनसंख्या के भरण-पोषण के अतिरिक्त खाद्यानों या निर्यात विदेशों के लिये किया जाता है। तकनीकी ज्ञान का प्रयोग कल-कारखानों की उत्पादन शक्ति में करके उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है। विश्व के विकास-शील एवं विकसित देश आज तकनीकी ज्ञान के लिये एक-दूसरे से राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित किए हुए हैं। विकासशील देशों में तकनीकी ज्ञान एवं नव-प्रवर्तन की न्यूनता होने से ये राष्ट्र आज भी पिछड़े हुए हैं।

उद्यमशीलता

नये विकास, तकनीकी ज्ञान एवं नव-प्रवर्तन आर्थिक विकास की दृष्टि से तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक की इन्हें व्यावसायिक रूप प्रदान न किया जाए। उद्यमशीलता (Entrepreneurship) के कारण विकसित देश अपनी चरम सीमा पर हैं जबकि विकसित देशों में उद्यमशीलता का अभाव है तथा जोखिम उठाने की क्षमता न होने के कारण उनका आर्थिक विकास रुका हुआ है। श्री यालेब्राजन ने स्पष्ट किया है कि "न तो आविष्कार की योग्यता और न केवल आविष्कार ही आर्थिक विकास को सम्भव बनाते हैं बल्कि यह तो उन्हें कार्य के रूप में परिणित की प्रबल इच्छा व जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है।"

व्यवसायिक ढाँचा

किसी भी देश का व्यवसायिक ढाँचा उस देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है। यदि देश में कल-कारखाने विकसित हैं तो उससे पूँजी का अर्जन होकर आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करते हैं। इसके विपरीत यदि व्यवसायिक ढाँचा पिछड़ा हुआ हो तो देश का आर्थिक विकास पिछड़ी हुई अवस्था में होता है। जापान में व्यवसायिक ढाँचे को सुदृढ़ बनाने के लिये वहाँ की सरकार नीतियों का निर्धारण करती है।

विदेशी पूँजी

किसी भी देश से आर्थिक विकास के लिये पूँजी का होना अति आवश्यक है। पूँजी यदि अपने ही देश से प्राप्त हो जाये तो ठीक है परन्तु यदि अपने देश में इतने साधन नहीं हैं कि पूँजी प्राप्त न हो सके तो विदेशी पूँजी द्वारा देश का विकास किया जा सकता है। विश्व में सिसली एक ऐसा देश है जहाँ पर यूरोप की अधिकांश राष्ट्र के द्वारा कल-कारखाने स्थापित किए गये हैं। यहाँ पर कोई कर (taxes) प्रणाली नहीं है इसलिये अधिकांश कारखाने यहाँ स्थित हैं। आज भी श्रीलंका विदेशी कम्पनियों को अपने देश में पूँजी लगाने को प्रोत्साहन दे रही है। भारत में विदेशी पूँजी ऋण के रूप में लगी हुई है। भारत में जितने भी बाँधों का निर्माण किया गया है वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund), विश्व बैंक तथा अन्य देशों से ऋण लेकर यहाँ के संसाधनों का विकास किया गया है। इस प्रकार कई देश हैं जो विदेशी पूँजी लगाकर अपने देश के संसाधनों का विदोहन करके आर्थिक विकास में सहायक होते हैं।

सामाजिक तथा सस्थागत तत्व

(मायर तथा वाल्डविन के अनुसार "आर्थिक विकास के लिए मनोवैज्ञानिक व सामाजिक आवश्यकताओं का होना उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार आर्थिक आवश्यकताओं का"। किसी भी देश की आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों में नूतन मूल्यों व संस्थाओं को अपनाने की कितनी प्रबल इच्छा है। प्रो० रागनर नर्से का कहना है कि "आर्थिक विकास का मानवीय मूल्यों सामाजिक प्रवृत्तियों, राजनीतिक दशाओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं से एक घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है।"

विकासशील देशों में जाति प्रथा, दुराचूत, संयुक्त परिवार प्रणाली, उत्तराधिकार का नियम, भूधारण की दोषपूर्ण व्यवस्था, भूमि व सम्पत्ति के प्रति मोह, अन्धविश्वास, रूढ़िवादिता, धार्मिक पाखण्ड, नवीन परिवर्तन के प्रति विरक्ति और उसका विरोध, सामाजिक अपव्यय तथा झूठी शान और शौकत जैसे तत्व आर्थिक विकास के मार्ग में हमेशा बाधाएँ उपस्थित करती रही हैं। इन देशों का आर्थिक विकास तब तक सम्भव नहीं हो सकता, जब तक की इनके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थाओं को नये सिरे से नव-निर्माण न कर दिए जाए।

स्थिर एवं कुशल प्रशासन

प्रो० डब्ल्यू आर्थर लुईस का मत है कि "कोई भी देश राजकीय सहयोग व उसका सक्रिय प्रोत्साहन पाये बिना, आज तक आर्थिक विकास नहीं कर सका है। यह कथन अपने में आज भी सत्य है और भावपूर्ण के लिए भी सत्य है और अल्प-विकसित अर्थव्यवस्था के लिए तो यह ध्रुव सत्य माना जाएगा।" देश के आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि देश का प्रशासन स्थिर हो अथवा कार्यकुशल हो अन्यथा विकास कार्यक्रम अधूरे व असफल बने रहेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय नीतियाँ

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सुरक्षा एवं स्थिरता व उदार नीतियों का होना अति आवश्यक है। विश्व रंग-मंच पर राजनैतिक शान्ति, स्थिरता के कारण ही एक देश दूसरे देश की मदद कर सकता है। राजनैतिक स्थिरता, विकसित देशों की नीतियाँ, पड़ोसी देशों का रूख, विदेशी व्यापार की सम्भावनाएँ और विदेशी पूँजी का प्रवाह इत्यादि आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। विकसित देशों की ऋण नीतियाँ, अनुदान की विधियाँ, तकनीकी सहायता इत्यादि एक-दूसरे की अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करती हैं तथा उसका प्रत्यक्ष प्रभाव उस देश के आर्थिक विकास पर पड़ता है।